श्री के०आर० मलकानी: फैसले बदले जा सकते हैं। यह जनता की मांग है।

MR. CHAIRMAN: The question is not of naming airports. It can be taken up separately...*(Interruptions)*

श्री एस०एस० अहलुवालिया: सभापति महोदय, अभी एक सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने बतायी है कि पटना एयरपोर्ट को सेकेंड फेज में रखा गया है। यह सब लोग जानते हैं कि पटना बिहार की राजधानी है और इसके साथ जुड़ा हुआ है बोधगया, जहां गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था और जुड़ा हुआ है पावापुरी, जहां जैनियों का बहुत बड़ा मंदिर है। पवित्र स्थान है और यह जुड़ा हुआ है सिखों के गुरु गोविन्द सिंह जी के जन्म स्थान पटना साहिब से, यह बुद्धिस्ट, जैनिस्ट और सिखों का एक सर्किट है और यह हिन्दुओं के लिए बहुत बड़ा पवित्र स्थान है और इस स्थान पर बहुत दिनों से हमारी मांग चल रही है कि यहां पर शुरूआत की जाए कि यहां इंटरनेशनल फ्लाइट चले। सभापति महोदय, सिर्फ यह धार्मिक नहीं, पर मिडिल ईस्ट में जो कामगार लोग जाते हैं उनकी संख्या देखी जाए तो उसमें बिहार के बहुसंख्यक लोग हैं। यहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट खोलने से कम से कम मिडिल ईस्ट को डायरेक्ट फ्लाइट जा सकती है, इसका प्रावधान किया जा सकता है। जब तक आप उसको इंटरनेशनल एयर पोर्ट का दर्जा नहीं देते तो कम से कम बुद्धिस्ट लोगों को आने के लिए या सिखों को आने के लिए या जैनियों को आने के लिए चार्टर फ्लाइट वहां लैंड कर सके, क्या उसका प्रावधान करने जा रहे हैं और उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे, यह कृपया सदन को बताएं?

श्री सी०एम० इब्राहीम: जहां तक फेज-2 है, यह कोई बड़ा लम्बा नहीं है। मार्च, 97 में पूरा हो जाएगा। जहां तक पटना का संबंध है...(व्यवधान)

श्री एस०एस० अहलुवालिया: सभापति महोदय, मैं इन्हें बतलाना चाहता हूं, यह कहते हैं कि पूरा हो जाएगा। पर यहां तो रोज पटना एयरपोर्ट बंद होता है क्योंकि नील गाय देखी जाती है। तो उसका क्या प्रावधान करेंगे ? चरखी दादरी जैसी दूसरी घटना पटना एयरपोर्ट पर घटेगी।...(व्यवधान) वहां पर रोज नील गाय देखी जाती है। Everyday they are announcing that a blue bull is sighted on the runway.

श्री सी०एम० इब्राहीम: अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं अवश्य देखूंगा। जहां तक सेकेंड फेज है, वह 1997 में पूरा हो जाएगा। जिन बातों और विचारों का आपने सुझाव दिया है, हम उनका अवश्य ही ध्यान रखेंगे।

MR. CHAIRMAN: Q. No. 163. Shri Iqbal Singh.

SHRI BALBIR SINGH: Sir, it is an important question about Punjab. Punjab is being discriminated against every time.

MR. CHAIRMAN: I have called Mr. Iqbal Singh.

SHRI SATISH PRADHAN: We would like to have a Half-An-Hour Discussion on this.

MR. CHAIRMAN: Please give notice. If there is time I will consider it.

Opening of New Hospitals in Punjab, Delhi, U.P., M.P. and Rajasthan

*163. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to open new hospitals in Punjab, Delhi, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan during the current year; and

(b) if so, location-wise details thereof; and the time by which construction of these hospitals is likely to be started?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) and (b) As Health is a State subject under the Constitution, the responsibility of establishing new hospitals is of the individual States.

Government has availed of assistance from the World Bank in promoting upgradation of health facilities including district hospitals in the States of Andhra Pradesh, Karnataka, West Bengal and Punjab as part of the State Health Systems Development Project. As far as the States of Delhi, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh are concerned, they have been asked to prepare revised proposals for seeking external assistance for upgrading their existing health facilities (including hospitals) at the

secondary level in districts located in backward/remote/tribal areas based upon the preliminary exercise already conducted by them. No proposal has been received from Rajasthan State so far.

The State Projects are developed through detailed discussions with the World Bank and past experience has shown that they take from 12 to 24 months to fructify, depending on the time taken on the design and formulation of the project by the State.

श्री इकबाल सिंह: श्रीमान्, अभी मंत्री जी ने अच्छा किया कि उत्तर सदन में पढ़कर सुना दिया। उन्होंने जो उत्तर दिया है—"एज हैल्थ इज स्टेट सब्जेक्ट।" यह कहने के बाद अपने उत्तर में लास्ट में यह कह रहे हैं कि — "दि स्टेट प्रोजेक्ट्स आर डवलप्ड थ्रू डिटेल्ड डिस्कशंस विद दि वर्ल्ड बैंक।" यह इन्होंने अपने आप ही कंट्राडिक्शन दे दी। पहले स्टेट सब्जेक्ट कह दिया, फिर उसके बाद थ्रू वर्ल्ड बैंक डिस्कशंस के लिए कह दिया।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देश की पोपुलेशन बहुत बढ़ गई है और देश में बीमारियां भी बहुत ज्यादा फैल गई हैं और इंसान के मन में एक भय है कि कौन सी बीमारी नई आ रही है और अभी-अभी कितने केसेज हो चुके हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप कब तक नए हॉस्पिटल इन स्टेट्स में-नौदर्न इंडिया में बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि इतने लोग जो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उनको अटेंड नहीं किया जाता है। अभी सफदरजंग हास्पिटल में सिर्फ 3600 पेशेंट्स डेली अटेंड किए जाते हैं जबकि वहां 10,000 के करीब लोग रोज़ आ रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कब तक आप नए हॉस्पिटल बनाने के लिए परवानगी देंगे?

SHRI SALEEM IQBAL SHERWANI: Mr. Chairman, Sir, as I have mentioned, 'Health' is a State Subject and the Central Government has no such policy of opening hospitals in the States. But looking at the problems of the people, what we have done is that we have held negotiations with the World Bank to upgrade the State health systems. We have done two phases of negotiations—Phase-I is for Andhra Pradesh and Phase-II is for Karnataka, Punjab and West Bengal. The aim of these negotiations is that since it is not possible for every person to come to Delhi, Madras, Mumbai or Calcutta for his treatment, health facilities should be made available in his own State. In order to upgrade the State health systems, we have negotiated with the World Bank. In Phase-I, Andhra Pradesh was given Rs. 600 crores. In Phase-II, Karnataka, Punjab and West Bengal were covered. Karnataka was given Rs. 546 crores; West Bengal was given Rs. 698 crores; and Punjab was given Rs. 425 crores. These amounts were given to upgrade the facilities at the State hospitals, be they primary health centres, community health centres, etc., so that a person could get himself checked and treated in his own district. It is likely that by this the pressure on hospitals located in the metros could get eased to some extent.

श्री इकबाल सिंह: मंत्री जी ने अच्छा किया कि नवें फाईव ईयर प्लान का प्रोग्राम भी बता दिया कि कितने सौ करोड़ रुपया दिया जाएगा। अभी-अभी हरियाणा में जो एयर-क्रैश की दुर्घटना हुई, उसमें देखने में आया कि हॉस्पिटल्स में कोई इंतजाम नहीं था। अभी कल अम्बाला में जो रेल दुर्घटना हुई, उसमें भी वहां पर बहुत कम लोगों को भरती किया गया और जिन्हें भरती किया गया, उनके लिए भी नई मेडिसिन्स वहां उपलब्ध नहीं थीं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नए मेडिसिन सिस्टम और मेडिसिन्स का इंतज़ाम आप हॉस्पिटल्स में कब तक करेंगे क्योंकि गरीब आदमी को तो मेडिसिन मिल ही नहीं रही है।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी: सर, जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को बताया कि ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनका मुद्दा ही यह है कि हम स्टेट हेल्थ सिस्टम्स को इतना अपग्रेड कर दें कि जो बातें आप बता रहे हैं कि फैसिलिटीज़ नहीं हैं, डॉक्टर्स में क्वालिफिकेशन्स नहीं है या लैब में फैसिलिटीज़ नहीं हैं, हम उनको अपग्रेड कर सकें। ये चीज़ें 2001 में जाकर कंप्लीट होंगी। अभी 96 में हमारे ये प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं और नवें फाईव ईयर प्लान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यह तो हम वर्ल्ड बैंक से असिस्टेंस ले रहे हैं और वर्ल्ड बैंक से असिस्टेंट लेकर हम इन कामों को पूरा कर रहे हैं। जहां तक

आपने हरियाणा का ज़िक्र किया, हम लोग यह कोशिश करते हैं कि जितनी मदद हम स्टेट की कर सकें, करें। मैंने हरियाणा के मुख्य मंत्री से भी इस संबंध में बात की है। जो भी दवाइयां हम भेज सकते हैं, जो भी एक्सपर्ट टीम हम भेज सकते हैं, जितने भी डॉक्टर्स हम वहां पहुंचा सकते हैं, उसमें हम कोई भी कोताही नहीं करते हैं और जैसे ही जरूरत महसूस होती है, उनको भेजने की कोशिश करते हैं।

श्री एस॰एस॰ सुरजेवाला: सभापति महोदय, अभी मंत्री जी ने अपनी पॉलिसी की व्याख्या करते हुए कहा कि वे वर्ल्ड बैंक से असिस्टेंस ले कर हॉस्पिटल खोलने में स्टेट्स की मदद कर रहे हैं। यह सर्वविदित है कि नेशनल हाईवेज़ पर रोज़ हज़ारों आदमी एक्सीडेंट्स में मौत के शिकार होते हैं और उससे कई गुना ज्यादा लोग जख्मी हालत में हैं। न वहां ब्लड बैंक हैं, न अच्छे हॉस्पिटल हैं। जो दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे हरियाणा से गुज़रता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वह बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहां इतनी देर में ब्लीडिंग से, हेमरेज से लोगों की डेथ हो जाती है। तो नेशनल हाईवेज़ पर, नेशनल हाईवे नंबर एक पर भी और दूसरे हाईवेज़ पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पचास-पचास, सौ-सौ किलोमीटर के फासले पर अच्छे हॉस्पिटल जिनमें सब तरह का प्रबंध हो ताकि एक्सीडेंट्स के केसेज में लोगों की जान बचाई जा सके... क्या मंत्री जी अपनी नीति में, प्रोग्राम में यह प्रावधान करेंगे कि वर्ल्ड बैंक की मदद से या अपनी मदद से इस तरह के अस्पताल खोले जायें?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी: सर, ऐसा अभी तो गवर्नमेंट का कोई विचार नहीं है। मगर दिल्ली में एक ट्रॉमा सेन्टर के बारे में हम जरूर सोच रहे हैं जिसके लिए एम्स के पास जमीन भी है और वह प्रोजेक्ट थोड़ा सा पीछे हो गया था जिसको अब तेज किया है। मैंने अपनी मिनिस्ट्री को यह डाइरेक्शन्स दी हैं कि तीन महीने के अन्दर उस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करके उसको शुरू कर दिया जाये। आपने जो वर्ल्ड बैंक वाली बात बताई, मैं कहना चाहता हूं कि हम कोशिश यह कर रहे हैं कि जो दिक्कत आज आ रही हैं लोगों के सामने अस्पतालों में फैसेलिटीज वगैरह की वह दूर कर सकें । कोई नया अस्पताल वर्ल्ड बैंक की मदद से नहीं बन रहा है। मगर जो हमारी एग्जिस्ट फैसेलिटीज हैं उनको हम अप-ग्रेड करना चाह रहे हैं और उनको इस लेवल पर लाना चाह रहे हैं कि आदमियों को बार-बार दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, चैन्नई में अपने इलाज के लिए न भागना पड़े, बल्कि अपने ही डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल में, गांव के अस्पताल में, कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर में ही अपना इलाज करा सकें।

श्री एस॰एस॰ सुरजेवाला: महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने यह पूछा था कि क्या अपनी नीति में यह प्रावधान करेंगे और क्या इस प्रोग्राम को चालू करेंगे? सर, जब तक मरीज दिल्ली पुहंचेगा तब तक ब्लडिंग से मर चुका होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि नेशनल हाइवेज पर जगह-जगह इस तरह के अस्पताल खोलने की जरूरत है, तो क्या गवर्नमेंट ऐसा करेगी?

SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI: There is no such thinking on the part of the Government at the moment to open hospitals on national highways. There is neither such a provision, nor are we thinking on those lines.

श्रीमती मालती शर्मा: मैं आपने माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि आप नये अस्पताल तो खोल रहे हैं लेकिन आपके जो पुराने डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल हैं वे केवल बूचड़खाना बन कर रह गये हैं। न उनमें दवाओं की सुविधा है और न वहां पेशेंट जाते हैं। आज हालत यह है कि जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम हैं उनमें तो मरीज अन्धा-धुन्ध जाते हैं पैसा देने के बावजूद भी और आपके अस्पतालों में फ्री दवाइयां मिलने पर भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां पर इमीटेशन दवाइयां मिल रही हैं और वह भी पैसा लेकर के। मरीजों से पैसा लेकर के बाहर से पट्टी मंगाई जाती है, अस्पतालों में इंजेक्शन लगाने के लिए स्प्रिट का फोहा तक नहीं मिलता है, तो आप उनकी दशा सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? साथ ही मैं कहना चाहती हूं कि आपने जो हैल्थ सेन्टर ग्रामीण क्षेत्रों में खोले हुये हैं, महदोय, मैं बता देना चाहती हूं कि मुजफ्फर नगर जिले में एक ऐसा ग्राम है जिसमें 12 महिलाएं प्रसूति के समय मर चुकी हैं। वहां भवन बना हुआ है लेकिन उसमें कोई डाक्टर नहीं बैठता है, वहां पर कोई नर्स नहीं है और वहां पर गांव वालों का कूड़ा पड़ता है। बार-बार सीएमओ को कहने के बावजूद भी वहां पर कोई डाक्टर पोस्ट नहीं किया जा रहा है, न उस हैल्थ सेन्टर को चलाया जा रहा है। आपके जो पुराने अस्पताल हैं और हैल्थ सेन्टर हैं, इनको सुचारू रूप से चालू करने के लिए क्या आपके पास कोई योजना है और आप क्या इस पर कोई ध्यान देंगे?

SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI: Sir, I would like to inform the hon.

Member that health is a State subject. The CMOs, the doctors, etc. are all under the State and the placement of doctors in every Community Health Centre or the Primary Health Centre is done by the State. *(Interruptions)*

श्री शिव चरण सिंह : उत्तर प्रदेश में केन्द्र का शासन है इसलिए आपको करना चाहिये...(व्यवधान)

SHRI SATISH AGARWAL: Mr. Minister, U.P. is under President's Rule. *(Interruptions)*

SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI: I am just answering that.

SHRI SATISH AGARWAL: Uttar Pradesh is under President's Rule. So, you arc answerable.

SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI: The hon. Member did not...*(Interruptions)* My reply to the question was that basically the funding that we were seeking from the World Bank was only to upgrade the State health system. It has nothing to do with hospitals. It is for upgrading the existing facilities. It is for providing equipment, asistancc and sending people for training. So, it is for upgrading the already existing facilities so that these conic up to a certain level and the people can get help.

श्री मोहम्मद आज़म खान : सभापति जी, यह सही हो सकता है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को स्टेट्स में अस्पताल बनाने की सुविधा न हो, बहुत से रूल्स ऐसे हैं जिनमें ये नहीं बना सकते। यह बात बहुत हद तक सही है। लेकिन अभी प्रश्न हुआ कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है और पिछले पांच महीनों से उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में दवा देने के लिए कोई पैसा नहीं है। क्या केन्द्र सरकार का कोई अधिकार नहीं बनता कि ऐसे प्रदेश में जहां इस वक्त भी राष्ट्रपति शासन है और पिछले चार-पांच महीनों से अस्पतालों के पास दवा देने के लिए कोई धन नहीं है, तो ऐसे प्रदेश का जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उसके लिए कोई धन की व्यवस्था का इन्तज़ाम आप करवायेंगे?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी: मोहतरम मेम्बर ने जो बात उठाई है, मैं इस चीज को गवर्नर साहब से टेक अप करूंगा और अगर कहीं पर भी कोई कमी है जिसको हम पूरी कर सकते हैं तो मैं उसको जरूर पूरी करूंगा।

MR. CHAIRMAN : The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Providing Local Purchase system to CGHS (Homoeo) Beneficiaries

*164. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether shortage of medicines exists in CGHS Homoeopathic Dispensaries/units in Delhi;

(b) if so, whether there is local purchase system in case of non-availability of medicines in dispensary/ unit;

(c) if so, the category of CGHS beneficiaries enjoying local purchase system benefit; and

(d) the reasons for not providing local purchase system to all the CGHS beneficiaries?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) and (b) Medicines are provided at the CGHS Homoeopathic dispensaries form the available stock at each dispensary. By and large no serious shortage of homoeopathic medicines has been encountered. In case of short-supply or non-avaibaility of any specific medicine, the dispensary can resort to local purchase from the open market against individual prescriptions until stocks are replenished.

(c) Local purchase is resorted to whenever the dispensary is unable to meet the requirements of a prescription or in case of sudden non-availability. This measure is used only occassionally as dispensaries have to by and large